Assistance for the development of Shrimp Farms, Hactheries and Feed mills

1185. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Central Government provide assistance to the farmers for the development of Shrimp farms, Hatcheries and Feed mills through the State Governments;

(b) if so, the details thereof;

(c) the numbr of farmers in Maharashtra who were provided Central assistance under the said scheme during the last three years with year-wise and district-wise details thereof; and

(d) the number of farmers likely to be provided the assistance during the remaining period of Eight Five Year Plan in the State and the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) and (b) Yes, Sir. The pattern of financial assistance provided by the Central Government to the farmers for the development of brackishwater shrimp culture is as under:—

(i) 25% of the capital cost and the total cost of inputs for the first crop, subject to a maximum of Rs. 30,000 per ha, is provided as subsidy to a beneficiary which will be shared between centre and the state on 50:50 basis.

(ii) Payment of stipend of Rs. 25/- per day and travelling allowance limited to Rs. 140/- per trainee for two months training, shared between central and State Governments on 50:50 basis.

(iii) Private/public sectors are provided asistance for establishment of Prawn Seed Hatcheries of 2-5 million capacity per annum to the extant of Rs. 1 lakh per hatchery or 10% of the cost whichever is lower. The subsidy is shared on 50:50 basis between Central and State Governments.

(iv) Financial assistance for establishment of Prawn feed plants with a capacity of 2000-4000 tonnes per annum @ Rs. 1.5 lakh per feed plant limited to 10% of the total estimated cost provided during 1991-92 and 1992-93 only.

(c) District-wise beneficiaries during the last 3 years in four districts where Brackishwater Fish Farmers Development Agencies have been established in Maharashtra are as stated below:

Year	District-wise and Year-wise no. of Beneficiaries			
	Thane	Raioad	Ratnagiri	Sindhudurg
1992-93	5	1	2	1
1993-94	4	9	1	2
1994-95	6	9	3	5
TOTAL:	15	19	6	8

(d) The target during the remaining two years of 8th Five Year Plan in the state is 400 beneficiaries.

हिन्दी के पाठकों की संख्या में गिरावट

1186. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दी के पाठकों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हिन्दी पुस्तकों के बढ़ते हुए मूल्य इसका एक कारण है;

(घ) क्या सरकार हिन्दी को बढ़ावा देने की दृष्टि से हिन्दी पुस्तकों के बढ़ते मूल्यों पर रोक लगाने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा॰ कृपासिंधु भोई): (क) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने सूचित किया है कि प्रकाशन उद्योग की सूचना के अनुसार हिन्दी पाठकों में कमी आयी है।

(ख) और (ग) पाठकों में कमी के कारणों में हिन्दी पुस्तक रखने वाली पुस्तक दुकानों की अपर्याप्त संख्या, हिन्दी प्रकाशनों द्वारा शामिल किए गए विषयों की सीमित श्रृंखला और पुस्तकों की कीमतों में वृद्धि शामिल है।

(घ) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और साहित्य अकादमी उचित कीमतों पर बड़ी संख्या में हिन्दी में पुस्तकें प्रकाशित कर रहे हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरकों की कमी

1187. **श्री रामजी लाल:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में कुल कितने उर्वरकों की कमी है और इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा कितने उर्वरक कारखानों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ग) राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये डी०ए०पी० कारखाने कहां-कहां लगाये जायेंगे; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा कुल कितनी राशि नियत की गयी है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव): (क) 1995-96 के दौरान देश में उर्वरकों का अनुमानित उत्पादन और खपत निम्न प्रकार है:—

(आंकड़े लाख टन में)

	एन	पी	के	कुल
खपत (अनुमानित)	107.54	35.60	13.51	156.65
उत्पादन (लक्ष्य)	86.27	26.67	—	112.94

देश में उर्वरकों के उत्पादन और खपत के अन्तर को मौसम के आरम्भ में उपलब्ध भण्डारों तथा आयातों से पूरा किया जाता है।

डी ए पी और एम ओ पी अनियंत्रित उर्वरक हैं तथा उनके आयात असरणीबद्ध है। यूरिया का आयात जो कि मूल्य तथा संचलन नियंत्रण के अन्तर्गत आता है, सरणीबद्ध है।

(ख) और (ग) प्रारम्भ की गई उर्वरक क्षमता संवर्धन योजना के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। (नीचे देखिए) नया डीएपी संयंत्र स्थापित नहीं किया जा रहा है।

(घ) मद्रास फर्टिलाइजर्स लि० तथा फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकौर लि० के मामले में सरकार ने 94 करोड़ रु० की कुल बजटीय सहायता प्रदान की है। क्षमता संवर्धन योजनाओं के लिए अपेक्षित शेष निधियों को क्रमशः एककों तथा वित्तीय संस्थानों से ऋण द्वारा आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाता है।

विवरण

देश में कार्यान्वयनाधीन उवरक परियोजनाओं के ब्यौरे

क्रमांक	कम्पनी / सहकारी समिति का नाम	स्थान	अनुमानित पूंजी लागत (रु० करोड़)	परिकल्पित उत्पादन उत्पाद क्षमता (लाख मी० टन प्रतिवर्ष)	आरम्भण की संभावित तारीख	बजटीय सहायता (रु० करोड़)
1	2	3	4	5	6	7
1.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि० (इफ्को)	आंवला (उ० प्र०) (विस्तार)	960.00	यूरिया 7.26	1.1.97	—
2.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि० (इफ्को)	कलोल (गुजरात) (विस्तार)	119.09	यूरिया 1.50	1.9.97	—
3.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि० (इफ्को) (इफ्को)	फुलपूर (उ०प्र०) (विस्तार)	993.00	यूरिया 7.26	20.1.99	—